दिसंबर तक भारत-ईयू एफटीए समझौता

यूरोपीय बाजार में 93 प्रतिशत भारतीय निर्यात को मिलेगी पहुंच, अगले साल फरवरी-मार्च से लागू होने की उम्मीद

नई दिल्ली, 22 जून भारत और यूरोपीय यूनियन (ईयू) के बीच लंबे समय से चल रही मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) की बातचीत अब अंतिम चरण में पहुंच गई है.

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और 27 देशों के यूरोपीय समूह के बीच दिसंबर तक एफटीए पर हस्ताक्षर होने की संभावना है, जबकि इसके अगले वर्ष फरवरी-मार्च से लागू होने की उम्मीद है. यह समझौता भारतीय निर्यातकों के लिए यूरोप के विशाल बाजार के द्वार और अधिक खोलने वाला साबित हो सकता है.

मुंबई में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ आयोजित एक कार्यक्रम में गोयल ने कहा कि समझौता लागू होने के बाद भारतीय उत्पादों को यूरोपीय बाजार में लगभग शून्य शुल्क के साथ प्रवेश मिलेगा. उन्होंने बताया कि एफटीए के तहत भारत के करीब 93 प्रतिशत निर्यात को ईयू के सदस्य देशों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी. इससे भारतीय उद्योगों, विशेष रूप से विनिर्माण, वस्त्र, इंजीनियरिंग और कृषि आधारित उत्पादों को बड़ा लाभ मिलने की संभावना है.

मंत्री ने कहा कि भारत और ईयू की संयुक्त आर्थिक शक्ति वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखती है. दोनों मिलकर दुनिया की कुल जीडीपी का लगभग 25 प्रतिशत और वैश्विक व्यापार का लगभग एक-तिहाई हिस्सा रखते हैं. ऐसे में यह समझौता केवल दोनों पक्षों के बीच व्यापार बढ़ाने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं और निवेश प्रवाह को भी मजबूती देगा.

> गोयल ने यह भी संकेत दिया कि भारत अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ भी व्यापार समझौतों को आगे बढ़ा रहा है. उन्होंने बताया कि कनाडा के साथ प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत जारी है और दोनों पक्ष इस वर्ष समझौते को अंतिम रूप देने के इच्छुक हैं. वहीं अमेरिका के साथ भी व्यापार समझौते को लेकर उच्चस्तरीय वार्ताएं चल रही हैं. इस अवसर पर मंत्री ने देश के निर्यात प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि वैश्विकआर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद अप्रैल-जून तिमाही में भारत का निर्यात लगभग 15 प्रतिशत बढ़ा है.

आईसीआईसीआई प्रू सिग्नेचर सिक्योर हुआ लॉन्च

यह प्लान धन सृजन की संभावना के साथ गारंटीड मैच्योरिटी बेनिफिट भी देता है

लाइफ कवर के साथ सिंगल-प्रीमियम प्रोडक्ट

भोपाल, 22 जून आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने आईसीआईसीआई प्रू सिग्नेचर सिक्योर लॉन्च किया है. यह भारतीय जीवन बीमा उद्योग का पहला यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान (यूलिप) है, जिसमें पहले से शामिल गारंटीड मैच्योरिटी बेनिफिट दिया गया है.

आईसीआईसीआई प्रू सिग्नेचर सिक्योर एक नॉन-पार्टिसिपेटिंग लिंक्ड इंडिविजुअल सेविंग्स लाइफ इंश्योरेंस प्लान है. इसे उन ग्राहकों के लिए बनाया गया है, जो टैक्स के लिहाज से बेहतर और गारंटीड फायदे चाहते हैं. इसका ढाँचा बेहद सरल है, एक बार निवेश कीजिए, पॉलिसी अवधि के दौरान लाइफ कवर का लाभ लीजिए और पाँच वर्ष पूर्ण होने पर मैच्योरिटी लाभ पाइए. मैच्योरिटी पर ग्राहक को फंड वैल्यू या गारंटीड मैच्योरिटी बेनिफिट में से जो अधिक होगा, वह मिलेगा. इससे निवेश पर निश्चित और भरोसेमंद रिटर्न मिलता है.

उदाहरण के लिए, मान लीजिए कोई 45 वर्षीय ग्राहक एकमुश्त निवेश का विकल्प चुनता है. वह आईसीआईसीआई प्रू सिग्नेचर सिक्योर में 5 लाख रुपए निवेश करके पॉलिसी अवधि के दौरान लाइफ कवर का लाभ ले सकता है. ग्राहक 6.25 लाख रुपए का लाइफ

भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता को मिली रफ्तार

जुलाई की टैरिफ समयसीमा से पहले सहमति की कोशिश

व्यापक व्यापार समझौते की दिशा में बड़ा कदम

नई दिल्ली, 22 जून भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) को आगे बढ़ाने की कवायद तेज हो गई है. दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को नई दिशा देने के उद्देश्य से इस सप्ताह नई दिल्ली में उच्चस्तरीय बैठकों का दौर शुरू होने जा रहा है.

भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने सोमवार को जानकारी दी कि अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जैमीसन ग्रीर नई दिल्ली पहुंचकर केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के साथ कई दौर की वार्ता करेंगे.

इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य प्रस्तावित व्यापार समझौते के पहले चरण को अंतिम रूप देना और अगले महीने लागू होने वाली महत्वपूर्ण टैरिफ समयसीमा से पहले लंबित मुद्दों पर सहमति बनाना है. सर्जियो गोर ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए कहा कि अमेरिका और भारत के बीच व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने के लिए मंत्री स्तर की कई बैठकें निर्धारित की गई हैं.

भारत और अमेरिका के बीच चल रही यह बातचीत अंतरिम व्यापार समझौते का हिस्सा है, जिसे भविष्य में व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते की आधारशिला माना जा रहा है. दोनों देश चरणबद्ध तरीके से व्यापारिक बाधाओं को कम करने और आर्थिक सहयोग को मजबूत बनाने पर काम कर रहे हैं.

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में संकेत दिया था कि उनके अमेरिकी समकक्ष व्यापार समझौते पर चर्चा के लिए भारत आ सकते हैं. वहीं, वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने भी स्पष्ट किया था कि आगामी वार्ताओं का प्रमुख उद्देश्य ढांचा समझौते को अंतिम रूप देना और व्यापक व्यापार समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ाना होगा सरकार के अनुसार दोनों देश अंतरिम समझौते से जुड़े लंबित विषयों को तेजी से सुलझाने की दिशा में काम कर रहे हैं.

> यदि दोनों देश निर्धारित समयसीमा के भीतर अंतरिम समझौते के पहले चरण पर सहमति बना लेते हैं, तो इससे व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग के नए अवसर खुलेंगे. साथ ही यह व्यापक भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की दिशा में एक महत्वपूर्ण और निर्णायक कदम साबित हो सकता है.

जून के अंत में चार दिन बैंक बंद

शाखाएं बंद, डिजिटल सेवाएं रहेंगी चालू

नकदी और लेनदेन की पहले करें तैयारी

नई दिल्ली,22 जून के आखिरी सप्ताह में बैंक ग्राहकों को अपनी वित्तीय योजनाएं समय रहते पूरी करनी होंगी. रिजर्व बैंक के अवकाश कैलेंडर के अनुसार 25 जून से 28 जून तक विभिन्न कारणों से कई शहरों में बैंक लगातार चार दिन बंद रहेंगे.

ऐसे में नकदी जमा करने, चेक क्लियरेंस, ड्राफ्ट बनवाने और शाखा से जुड़े अन्य जरूरी कार्यों को पहले ही निपटाने की सलाह दी गई है. बैंक अवकाशों की यह श्रृंखला मुहर्रम, चौथे शनिवार और रविवार की छुट्टियों के कारण बन रही है. 25 जून को मुहर्रम के अवसर पर विजयवाड़ा में बैंक बंद रहेंगे. इसके अगले दिन 26 जून को मुहर्रम के कारण नई दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, कानपुर, पटना, भोपाल, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद सहित कई प्रमुख शहरों में बैंकिंग सेवाएं प्रभावित रहेंगी.

इसके बाद 27 जून को महीने का चौथा शनिवार होने के कारण देशभर में बैंकों की नियमित छुट्टी रहेगी. वहीं 28 जून को रविवार होने से सभी बैंक बंद रहेंगे. लगातार पड़ने वाली इन छुट्टियों के कारण शाखाओं में होने वाले कई कार्य चार दिनों तक प्रभावित रह सकते हैं. जिन ग्राहकों को बड़ी राशि जमा करनी है, चेक जमा कराने हैं, ऋण संबंधी दस्तावेज पूरे करने हैं या किसी अन्य शाखा आधारित सेवा की जरूरत है, उन्हें अवकाश शुरू होने से पहले ही अपना काम पूरा कर लेना चाहिए.

बिना टिकट यात्रा पर अब 500 रुपये से शुरू होगा जुर्माना

नयी दिल्ली, 22 जून. रेलवे बोर्ड ने यात्रियों की सुरक्षा, अनुशासन और व्यवस्था सुधारने के लिए 2013 के बाद पहली बार संशोधित किए दंडात्मक नियम, गलत टिकट, कोच नियम उल्लंघन और अवैध गतिविधियों पर बढ़ी सख्ती

भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और ट्रेन संचालन में अनुशासन बनाए रखने के उद्देश्य से अपने नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं. रेलवे बोर्ड द्वारा जारी नए प्रावधानों के अनुसार अब बिना टिकट या गलत टिकट के साथ यात्रा करने वालों पर पहले की तुलना में अधिक सख्त कार्रवाई की जाएगी. यह संशोधन वर्ष 2013 के बाद पहली बार किया गया है.

ट्रंप टैरिफ 2.0 का नया खेल प्रारंभ

धारा 301 के तहत नए टैरिफ ढांचे की तैयारी

कुछ देशों पर टैक्स घटेगा, कुछ पर बढ़ेगा

नई दिल्ली ,22 जून अमेरिका में व्यापार नीति एक बार फिर बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है, जहां पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्तावित 'टैरिफ 2.0' मॉडल के तहत वैश्विक व्यापार समीकरण बदलने की तैयारी है.

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले लागू किए गए वैश्विक टैरिफ को अवैध ठहराए जाने के बाद ट्रंप प्रशासन अब 1974 के ट्रेड एक्ट की धारा 301 का सहारा लेकर नई टैरिफ व्यवस्था तैयार कर रहा है.

नई रणनीति के तहत अमेरिका कई देशों के व्यापारिक व्यवहार की

जांच कर रहा है, जिसमें 'फोर्स्ड लेबर' और 'अतिरिक्त औद्योगिक क्षमता' जैसे आरोप शामिल हैं. जांच के नतीजों के आधार पर संबंधित देशों पर अतिरिक्त आयात शुल्क लगाया जा सकता है. इस कदम का उद्देश्य टैरिफ को कानूनी रूप से अधिक मजबूत बनाना बताया जा रहा है, ताकि इसे अदालतों में चुनौती देना कठिन हो.

इसके विपरीत, कुछ देशों पर दबाव बढ़ने की आशंका है. सिंगापुर जैसे व्यापारिक साझेदार पर अतिरिक्त शुल्क लागू होने का जोखिम बताया जा रहा है, जिससे उसकी निर्यात स्थिति प्रभावित हो सकती है

> रिपोर्ट्स के अनुसार, इस नई व्यवस्था में सभी देशों पर समान असर नहीं पड़ेगा. जुलाई के अंत में मौजूदा अस्थायी 10 प्रतिशत वैश्विक टैरिफ समाप्त होने के बाद कुछ देशों पर शुल्क घटने की संभावना है, जबकि कुछ पर बढ़ोतरी हो सकती है. फिलीपींस जैसे देशों के लिए राहत की संभावना है, जहां टैरिफ मौजूदा स्तर से घटकर लगभग 12.5 प्रतिशत तक आ सकता है. वहीं दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों पर भी जांच के आधार पर शुल्क में बदलाव देखने को मिल सकता है.

सोना-चांदी की कीमतों में उछाल

सोना हुआ 800 रुपए तक महंगा, चांदी में 4000 रुपए प्रति किलो की जोरदार तेजी

नई दिल्ली,22 जून 2026 भारतीय सर्राफा बाजार में सोने और चांदी दोनों की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिला है. वैश्विक बाजारों में बढ़ती मांग, भू-राजनीतिक तनाव और डॉलर की कमजोरी के चलते कीमती धातुओं के दामों में मजबूती आई है. घरेलू बाजार में 22 कैरेट और 24 कैरेट सोना महंगा हो गया है, जबकि चांदी की कीमतों में भी जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई है.

रिपोर्ट्स के अनुसार, 24 कैरेट

सोना करीब 14,700 से 14,800 प्रति 10 ग्राम के बीच कारोबार कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोना भी इसी अनुपात में बढ़कर ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है. अनुमानित तौर पर सोने की कीमतों में लगभग ?800 प्रति 10 ग्राम तक की बढ़त देखी गई है. इस तेजी के चलते ज्वेलरी बाजार में ग्राहकों की खरीदारी पर असर पड़ सकता है, खासकर शादी और त्योहारों के सीजन से पहले.

वहीं चांदी ने इस बार सोने से भी तेज रफ्तार दिखाई है. चांदी की कीमतों में करीब ?4000 प्रति किलोग्राम तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. विशेषज्ञों का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चल रही अनिश्चितताओं और कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव का सीधा असर कीमती धातुओं पर पड़ रहा है.

अगस्त तक ईंधन आपूर्ति सुरक्षित

एचपीसीएल ने खरीदा 40 लाख बैरल तेल

अफ्रीका और लैटिन अमेरिका से बढ़ा आयात

नई दिल्ली , 22 जून मिडिल ईस्ट में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर मंडरा रहे संकट के बीच भारत के लिए राहत भरी खबर है.

देश की प्रमुख तेल रिफाइनरियों ने कच्चे तेल और रसोई गैस (एलपीजी) का पर्याप्त भंडार जुटा लिया है, जिससे कम से कम अगस्त 2026 तक घरेलू जरूरतों को पूरा करने में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी. उद्योग सूत्रों के अनुसार भारतीय तेल कंपनियों ने पिछले कुछ सप्ताह में आक्रामक खरीदारी करते हुए कच्चे तेल और एलपीजी की बड़ी मात्रा सुरक्षित कर ली है. इस रणनीति के तहत कंपनियों ने मध्य पूर्व के अलावा अन्य वैश्विक बाजारों से भी ईंधन खरीदकर आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाया है. जानकारों का कहना है कि भारत की रिफाइनरियां फिलहाल पर्याप्त स्टॉक के साथ काम कर रही हैं.

भारतीय शेयर बाजारों में आई तेजी

291.17 अंक पर आया सेंसेक्स

89.80 अंक पर पहुंचा निफ्टी

मुंबई, 22 जून पिछले कारोबारी दिवस की गिरावट से उबरते हुए घरेलू शेयर बाजारों में सोमवार को तेजी रही और बीएसई का सेंसेक्स 291.17 अंक (0.38 प्रतिशत) चढ़कर 77,094.07 अंक पर बंद हुआ.

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 सूचकांक भी 89.80 अंक यानी 0.37 प्रतिशत ऊपर

24,102.90 अंक पर बंद हुआ. अमेरिका और ईरान के बीच अंतिम शांति समझौते के लिए चल रही वार्ता में प्रगति की खबरों से बाजार में निवेशकों का विश्वास मजबूत हुआ है.

वृहत बाजार में भी तेजी रही. निफ्टी मिडकैप-50 सूचकांक 0.37 प्रतिशत और स्मॉलकैप-100 सूचकांक 0.60 प्रतिशत की बढ़त में बंद हुआ.

> सेंसेक्स की कंपनियों में टेक महिंद्रा का शेयर दो प्रतिशत के करीब चढ़ा. सन फार्मा, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंफोसिस और बीईएल में भी एक प्रतिशत अधिक तेजी रही. बजाज फिनसर्व, कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक, बजाज फाइनेंस, भारतीय स्टेट बैंक, भारती एयरटेल और आईसीआईसीआई बैंक के शेयर भी हरे निशान में रहे.

समाचार विशेष

पंजाब की खिचड़ी कश्मीर में पका रहे सिद्धू?

श्रीनगर. पूर्व क्रिकेटर और कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने सोमवार को यहां राष्ट्रीय सम्मेलन के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात की.

राष्ट्रीय सम्मेलन सूत्रों के अनुसार, सिद्धू ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री से उनके गुपकर स्थित आवास पर मुलाकात की. सूत्रों ने बताया कि दोनों नेताओं ने देश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति, जम्मू-कश्मीर में हो रहे घटनाक्रम और आपसी हित के अन्य विषयों पर चर्चा की.

नवजोत सिंह सिद्धू ने फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात के बाद उनकी जमकर तारीफ की है. साथ ही उन्होंने फारूक को भारतीय राजनीति का दिग्गज करार दिया है. साथ ही उन्होंने कहा कि फारूक अब्दुल्ला देश की राजनीति में प्रभावशाली आवाजों में से एक हैं. साथ ही उन्होंने फारूक अब्दुल्ला द्वारा जनता के मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखने और खुलकर बोलने पर तारीफ की.

इस मुलाकात को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू ने भी अपने सोशल मीडिया पर जानकारी दी है. एक पोस्ट में उन्होंने बताया कि फ़ारूक़ अब्दुल्ला साहब से उनके घर पर मुलाक़ात की. हमारी यात्रा को आसान बनाने के लिए उनका शुक्रिया अदा किया. भारतीय राजनीति की एक बड़ी हस्ती, जिनमें सच बोलने की हिम्मत है और जो कश्मीर के लोगों की सच्ची धर्मनिरपेक्ष आवाज हैं.

सिद्धू ने अपने इस पोस्ट में मुलाकात की शानदार झलकियां भी दिखाई हैं. नवजोत सिंह सिद्धू ने फारूक अब्दुल्ला के साथ दो फोटो शेयर करते हुए इस मुलाकात के बारे में जानकारी दी है. साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री का अपनी कश्मीर यात्रा में मदद के लिए शुक्रिया भी अदा किया है.

इस वजह से महत्वपूर्ण है यह मुलाकात

नवजोत सिंह सिद्धू और फारूक अब्दुल्ला के बीच इस मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है. अपने परिवार संग सिद्धू कश्मीर में छुट्टियां मनाने के लिए पहुंचे हैं. इस बीच उन्होंने फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात कर राजनीतिक हलकों में चर्चाएं छेड़ दी हैं. दोनों की राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीति में अहम भूमिका को देखते हुए सिद्धू की यह यात्रा चर्चा के केंद्र में है.

गोस्वामी-द्विवेदी के लिए बेचैन ममता

क्यों चाहती हैं स्वरूप और कुसुम को अपने पास?

कोलकाता. पश्चिम बंगाल की राजनीति में पहले टीएमसी की टूटने की खबर सामने आई. फिर अब ममता बनर्जी की सुरक्षा को लेकर एक खबर सामने आई है. जिसने बंगाल की राजनीति में एक और तड़का लगा दिया है.

इस मामले को उठाया है टीएमसी नेता डेरेक ओ ब्रायन ने उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें वह दावा कर रहे हैं कि ममता की सुरक्षा को लेकर सरकार बिल्कुल सावधान नहीं है. इसलिए वह खुद अपनी गाड़ी घर के मुख्य गेट के सामने खड़ी कर दिए हैं. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि स्वरूप गोस्वामी और कुसुम कुमार द्विवेदी को भी अचानक हटा दिया गया.

ममता बनर्जी की पीएसओ को हटाने पर बवाल- पश्चिम बंगाल की राजनीति में दो सुरक्षाकर्मी स्वरूप गोस्वामी और कुसुम कुमार द्विवेदी जिन्हें उनकी अलग जगह पोस्टिंग कर दी गई है तो ममता बनर्जी नाराज हो गई हैं. खबर है कि ममता बनर्जी ने इन दोनों को हटाने के सरकारी आदेश पर अपनी नाराजगी जताई है और उन्हें ही अपनी सुरक्षा में रखने की जिद ठान ली है. खबर के मुताबिक, स्वरूप गोस्वामी और कुसुम कुमार द्विवेदी कोई आम सुरक्षाकर्मी नहीं हैं. ये दोनों पिछले 20 सालों से ममता बनर्जी के पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर (पीएसओ) के तौर पर काम कर रहे हैं. इन दो दशकों में उन्होंने ममता बनर्जी की हर छोटी-बड़ी सुरक्षा जरूरतों को बारीकी से समझा है.

क्या सुलझेगा यह नया विवाद?

अभी स्थिति यह है कि ममता बनर्जी अपनी जिद पर अड़ी हैं, जबकि राज्य सचिवालय अपने प्रशासनिक स्टैंड से पीछे हटने को तैयार नहीं है. प्रशासन का दावा है कि ममता बनर्जी को जेड+' कैटेगरी की सुरक्षा मिल रही है और उसमें कोई कमी नहीं है. हालांकि, ममता की नाराजगी और पुराने पीएसओ के लिए उनकी बेचैनी ने इस पूरे मुद्दे को सियासी रंग दे दिया है. अब सबको देखना यह होगा कि क्या सरकार ममता बनर्जी की पसंद को प्राथमिकता देती है या फिर प्रशासनिक नियमों का ही सख्ती से पालन होता है.

भीड़ नहीं, हमें ईमानदारी चाहिए

चेन्नई. तमिलनाडु के पूर्व भाजपा अध्यक्ष के. अन्नामलाई ने अपने नई राजनीतिक पार्टी को लेकर बड़ा अपडेट दिया है. उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर वीडियो पोस्ट किया.

पोस्ट में उन्होंने बताया कि हाल ही में शुरू किया गया उनका वी द लीडर्स मूवमेंट जुलाई तक एक राजनीतिक पार्टी बनने की दिशा में सही रास्ते पर है और इसका लक्ष्य 50 लाख सदस्य बनाना है.

बीजेपी तमिलनाडु के पूर्व अध्यक्ष के. अन्नामलाई ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है. वीडियो में उन्होंने कहा कि आज कई राजनीतिक संगठन दावा कर सकते हैं कि उनके पास एक करोड़, 50 लाख, 30 लाख या डेढ़ करोड़ सदस्य हैं, लेकिन हम उस होड़ में शामिल नहीं हैं. हमारे राजनीतिक आंदोलन में सबसे जरूरी चीज ईमानदारी है. जिस दिन 'वी द लीडर्स मूवमेंट' की वेबसाइट पर वॉलंटियर्स की संख्या 50 लाख तक पहुंच जाएगी, हम इस बारे में बात करेंगे. जब तक लोग खुद हमसे राजनीतिक पार्टी बनने के लिए नहीं कहेंगे, हम अपना काम करते रहेंगे.

विशेष उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज

अखिलेश का 'ब्राह्मण कार्ड' माया को याद आया 2007

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं. सभी पार्टी अपने-अपने तरीके से लोगों को एकजुट करने के तरीके में लग गए हैं. एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री मायावती प्रदेश में ओबीसी नेताओं के साथ बैठक की. वहीं, दूसरी तरफ सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ब्राह्मण नेताओं के साथ मीटिंग कर रहे हैं.

विधानसभा चुनाव से पहले ब्राह्मणों के साथ बैठक करके अखिलेश यादव ने बड़ा संदेश दिया है. मिशन 2027 को और पुख्ता करने के लिए अखिलेश ने ब्राह्मण कार्ड खेला है. इस बैठक में वर्तमान विधायकों-सांसदों के साथ-साथ कई पूर्व विधायक और सांसदों को भी बुलाया गया.

विधानसभा चुनाव से पहले सपा का ब्राह्मणों के साथ बैठक करना एक रणनीति का हिस्सा है. भाजपा सरकार में सीएम योगी के कार्यकाल के दौरान राज्य में ब्राह्मण वोटरों की नाराजगी खबरों ने काफी सुर्खियां बटोरी. इसके बाद से ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार ब्राह्मणों को अपने पाले में लाने की कवायद में जुट गए हैं और बैठकों के जरिए खुद को ब्राह्मणों का सबसे बड़ा हिमायती दिखाना चाहते हैं.

ओबीसी वोटर्स पर मायावती की नजर- सपा ब्राह्मण कार्ड खेल रही है तो बसपा प्रमुख मायावती ओबीसी को अपने पाले में लाने की कोशिशों में जुटी हैं. मंगलवार को मायावती ने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि वे 2027 विधानसभा चुनावों से पहले प्रदेश में ओबीसी का समर्थन जुटाने की कोशिश करें. ओबीसी को अपने पाले में करके मायवती 2007 के चुनावी नतीजे दोहराने की तैयारी करती दिख रही हैं.

ओबीसी योगदान को फिर दोहराने के प्रयास

अपने एक्स हैंडल पर प्रेस विज्ञप्ति साझा करते हुए मायावती ने इसकी जानकारी दी. विज्ञप्ति के अनुसार, बी.एस.पी. प्रमुख बहन कु. मायावती द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी समाज) को सन् 2007 में यूपी में बी.एस.पी. की पहली पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में उनके ऐतिहासिक योगदान को एक बार फिर सन् 2027 के विधानसभा आमचुनाव में दोहराने के प्रयास में यहां जारी बैठकों में पिछले दिशा-निर्देशानुसार उनकी जमीनी तैयारियों व जनाधार को बढ़ाने सम्बंधी उनके कार्यकलापों आदि की गहन समीक्षा तथा चुनाव सम्बंधी विशेष निर्देश.